अनुबंध II

सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय[1]: अप्रैल 2022 से मार्च 2025

वर्ष	तारीख	विषय
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग		
2022-23	1 जून 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश 2022 जारी किए गए, जिसमें कवर की गई संस्थाओं के लिए अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत डेरिवेटिव (एनसीसीडी) (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेनों के लिए विचरण मार्जिन का विनिमय अनिवार्य किया गया था।
	16 जून 2022	अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान हेतु दिशा-निदेश निर्धारित करते हुए मसौदा निदेश जारी किए गए।
	17 फरवरी 2023	सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) उधार देने और उधार लेने की अनुमति देने के लिए मसौदा निदेश जारी किए गए। अंतिम निदेश 27 दिसंबर 2023 को जारी किए गए थे।
2023-24	28 दिसंबर 2023	जी-सेक पर बॉण्ड फॉरवर्ड शुरू करने के लिए मसौदा निदेश जारी किए गए।
	3 जनवरी 2024	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा की गई और इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य भागीदारों के संदर्भ में उत्पादों में एकरूपता लाने के लिए संशोधित निदेश जारी किए गए।
	5 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और संशोधित निदेश जारी किए गए, सभी प्रकार के लेनदेनों - ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड - के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को एक ही मास्टर निदेश के तहत समेकित किया गया, अनुमत एफएक्स डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया गया और उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया गया ताकि उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं के साथ सक्षम बनाया जा सके और वे अपने जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकें।
2024-25	29 अप्रैल 2024	इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए मसौदा मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म) निदेश 2024 जारी किए गए।
	8 मई 2024	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश 2024 जारी किए गए, जिसमें शामिल संस्थाओं को अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेनों के लिए प्रारंभिक और विचरण मार्जिन का आदान-प्रदान करना अनिवार्य किया गया।
	21 फरवरी 2025	भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश 2025, बीमा निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए जारी किए गए थे। इन वायदा संविदाओं की शुरूआत से उन डेरिवेटिव के कुशल मूल्य निर्धारण में भी मदद मिलेगी जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करते हैं।
विदेश मुद्रा विभाग		
2022-23	22 अगस्त 2022	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत विदेशी निवेश ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक/टिप्पणियों के आधार पर, तर्कसंगत 'विदेशी निवेश विनियमन' जारी किए गए।
2023-24	26 दिसंबर 2023	फेमा, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए मसौदा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी किए गए।
2024-25	2 जुलाई 2024	फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उदार बनाने के लिए 'विदेशी व्यापार पर मसौदा विनियमन और निदेश' जारी किए गए।

[1] इसमें नई/बड़ी विनियामक नीतियों के साथ-साथ वृद्धिशील परिवर्तन और मौजूदा दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा शामिल है, जो मसौदा परिपत्रों, रिपोर्टों, चर्चा पत्रों और हितधारक सहभागिताओं के माध्यम से परामर्श के बाद की जाती है। इस अनुबंध में शामिल कुछ मसौदा परिपत्रों/मसौदा दिशा-निर्देशों/चर्चा पत्रों के लिए सार्वजनिक परामर्श अभी भी जारी है।

वर्ष	तारीख	विषय
विनियमन विभाग		
2022-23	27 जुलाई 2022	जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर चर्चा पत्र।
	2 सितंबर 2022	डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश।
	11 अक्टूबर 2022	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा।
	16 जनवरी 2023	प्रत्याशित हानि (ईएल) - बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र।
	25 जनवरी 2023	दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र।
	17 फरवरी 2023	बासेल III के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश।
2023-24	28 अप्रैल 2023	धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी संबंधी मास्टर निदेश में संशोधन।
	4 मई 2023	केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन - वायर ट्रांसफर पर अनुदेश।
	8 जून 2023	डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश।
	26 जून 2023	परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश।
	18 अगस्त 2023	• समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित वैयक्तिक ऋणों पर अस्थिर ब्याज दर का पुनर्निर्धारण। • उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार (जुर्माना)।
	12 सितंबर 2023	वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संबंधी मास्टर निदेश।
	13 सितंबर 2023	'जिम्मेदार उधार आचरण - वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' पर परिपत्र।
	21 सितंबर 2023	• इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार के संबंध में मसौदा मास्टर निदेश। • मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासेल III पूंजीगत फ्रेमवर्क पर विवेकपूर्ण विनियमन, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) निदेश, 2023।
	17 अक्टूबर 2023	पीएमएल नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और एफएटीएफ सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन।
	26 अक्टूबर 2023	• वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा मास्टर निदेश। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर अनुदेशों की समीक्षा।
	1 जनवरी 2024	बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावी जमाराशियों पर परिपत्र - संशोधित अनुदेश।
	2 जनवरी 2024	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा लाभ को मुख्यालय में विप्रेषित करने के बारे में मसौदा परिपत्र।
	15 जनवरी 2024	• क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण मानदंडों पर मसौदा परिपत्र – सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)। • आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य पर मसौदा परिपत्र।

वर्ष	तारीख	विषय
2023-24	9 फरवरी 2024	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) पर भारतीय बैंकों की भागीदारी पर परिपत्र।
	28 फरवरी 2024	जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर मसौदा प्रकटीकरण ढांचा, 2024।
	7 मार्च 2024	मास्टर निदेश में संशोधन – क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और आचरण संबंधी निदेश, 2022 – संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ अद्यतन दिशानिर्देश, उपर्युक्त मास्टर निदेश के अनुबंध के रूप में जारी किए गए और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए गए।
	21 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिये स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता के लिये बहुप्रयोजनीय ढाँचा।
2024-25	5 अगस्त 2024	ऋण में आदर्श जोखिमों के प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मसौदा परिपत्र।
	4 अक्तूबर 2024	'व्यवसाय के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन' पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया, जिसमें 20 नवंबर, 2024 तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई। 26 मई, 2016 को जारी मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएँ) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 4 और 5, बैंकों द्वारा निवेश के लिए व्यवसाय के स्वरूप और विवेकपूर्ण विनियमन पर विनियमों को समेकित करते हैं। मसौदा परिपत्र इन विनियमों की समीक्षा करता है, जिसका उद्देश्य बैंकों के मुख्य व्यवसाय को अन्य जोखिम वाले गैर-मुख्य व्यवसायों से अलग रखना है, साथ ही बैंकों को वित्तीय सेवाओं/गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों और वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश करने के लिए परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना है।
फिनटेक विभाग		
2023-24	15 जनवरी 2024	फिनटेक क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए मसौदा ढांचा जारी किया गया।
2024-25	30 मई 2024	'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन (संगठनों) के निर्धारण के लिए रूपरेखा' (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) की घोषणा 30 मई 2024 को की गई, जो 15 जनवरी 2024 को इस उद्देश्य के लिए जारी मसौदे पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के आधार पर की गई थी।
पर्यवेक्षण विभाग		
2022-23	6 मार्च 2023	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश/पीएसबी की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा के अंतर्गत कारोबार कवरेज संबंधी मानदंड जारी किए गए थे।
2023-24	10 अप्रैल 2023	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में मास्टर निदेश जारी किया गया।
	13 अक्टूबर 2023	पीएसबी को शून्य अग्रिम वाली शाखाओं और अनर्जक आस्ति (एनपीए) वसूली शाखाओं की लेखा परीक्षा के लिए उनके एसबीए को देय पारिश्रमिक का निर्णय करने के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया था।
	7 नवंबर 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश जारी किए गए।
	15 जनवरी 2024	राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय

वर्ष	तारीख	विषय
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग		
2022-23	19 मई 2022	एटीएम में अंतर-परिचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) को सक्षम किया गया।
	26 मई 2022	भारत बिल भुगतान प्रणाली पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।
	16 जून 2022	ई-मैंडेट ढांचे के कार्यान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा पर, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के लिए छूट की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति लेनदेन कर दी गई थी।
	28 जुलाई 2022	भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय-सीमा की समीक्षा की गई।
	17 अगस्त 2022	भुगतान प्रणालियों में प्रभारों पर चर्चा पत्र जारी किया गया।
2023-24	2 जून 2023	भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मसौदा मास्टर निदेश जारी किए गए।
	7 जून 2023	व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया।
	5 जुलाई 2023	डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया।
	24 अगस्त 2023	ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतानों के लिए लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई।
	31 अक्टूबर 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन – सीमा पार' पर परिपत्र जारी किया गया।
	12 दिसंबर 2023	ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत एएफए के बिना किए जाने वाले अनुवर्ती आवर्ती लेनदेन की सीमाएं निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ाई गईं।
	20 दिसंबर 2023	सीओएफटी – कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन सक्षम किया गया।
	29 दिसंबर 2023	भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का वर्धन कर उसे दो और वर्षों की अवधि यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया।
	23 फरवरी 2024	प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी 2024	भारत बिल भुगतान प्रणाली पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	6 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था' पर परिपत्र जारी किया गया।
2024-25	16 अप्रैल 2024	भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन पर मसौदा निर्देश जारी किए गए। इसमें भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन पर नए मसौदा निर्देश शामिल हैं, जिसमें भौतिक बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ भुगतान एग्रीगेटर्स पर मौजूदा निर्देशों में संशोधन शामिल हैं।
	30 जुलाई 2024	'गैर-बैंक पीएसओ के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश' जारी किए गए।
	31 जुलाई 2024	• डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र पर मसौदा रूपरेखा जारी की गई। • आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचपॉइंट ऑपरेटरों की उचित जांच पर मसौदा निर्देश जारी किए गए।
	27 दिसंबर 2024	तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लिकेशन के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी वाले पीपीआई से/के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान सक्षम किए गए।
	7 फरवरी 2025	सीमापार कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए एएफए पर मसौदा निर्देश जारी किए गए।
	28 मार्च 2025	एटीएम नेटवर्क को एटीएम विनिमय शुल्क तय करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, एटीएम लेनदेनों के लिए अनिवार्य नि:शुल्क लेन-देनों के उपरांत अनुमत अधिकतम ग्राहक प्रभारों को संशोधित किया गया।